



## रिहन्द बांध परिक्षेत्र की पर्यावरणीय समस्याएं, दुष्प्रभाव एवं संरक्षण के उपाय

डॉ० शिव प्रसाद

एसोसिएट प्रोफेसर- भूगोल विभाग, सतीश चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया (उ०प्र०), भारत

Received- 05.12.2019, Revised- 10.12.2019, Accepted - 14.12.2019 E-mail: -aaryvart2013@gmail.com

**सारांश :** साठ के दशक में रिहन्द बांध की नींव रखते हुए, तब के राजनेताओं, खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस पुनीत कार्य के नतीजों का कोई शायद ही ख्याल आया होगा कि देश की ऊर्जा राजधानी खड़ी करने के जुनून में उत्तर प्रदेश के सोनमद्र (तत्कालीन मिर्जापुर जिला) और मध्य प्रदेश के सिंगरौली को वायु, जल, भूमि और मिट्टी के प्रदूषण तथा वहां के मूल निवासियों के तीन – तीन बार के विस्थापन जैसी मानवीय प्रताड़ना का घर बना दिया जाएगा। कोयला भंडार से परिपूर्ण इस क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली पानी के लिए 1960 के दशक में रिहंद नदी पर बांध बनाया गया था। आज रिहन्द परिक्षेत्र में 21000 मेगावाट की 10 थर्मल पावर प्लांट और नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड (एन.सी.एल.) समेत निजी कंपनियों की 16 कोयला खदानें संचालित हैं। इन खदानों से लगभग 7 करोड़ मैट्रिक टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जाता है। एन.सी.एल. के चेयरमैन पीवकेव सिन्हा ने 10 दिसंबर 2018 के एक कार्यक्रम में कहा था कि रिहंद परिक्षेत्र में 2021 तक 10 करोड़ 80 लाख मैट्रिक टन और 2023-24 के लिए 111 करोड़ पचास लाख मैट्रिक टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में मोरवा बाजार, पीटरवाह, सुलियरी, सिधौली, बरका और महुली आदि में कोल-ब्लॉक से उत्पादन करने की तैयारी चल रही है। देश के कुल कोयला भंडारों का 8: मध्यप्रदेश में है, जिसमें सिंगरौली सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। जिले के चितरंगी क्षेत्र में चकरिया और गुशार पहाड़ में सोने के अयस्क का पर्याप्त भंडार का पता चला है। 147 हेक्टेयर में सरकार ने खनन का निर्णय भी ले लिया है। प्रस्तुत शोध-आलेख में भारत के ऊर्जा की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, रिहंद बांध परिक्षेत्र की पर्यावरणीय समस्याएं और उसके दुष्प्रभावों का आंकलन करते हुए वहां के पर्यावरण को संरक्षित करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है।

**कुंजीभूत शब्द- रिहंद बांध परिक्षेत्र, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ताप विद्युत संयंत्र, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण।**

रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश के सोनमद्र जिले में पिपरी स्थित विंध्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण इलाका है। जहां हरिजन आदिवासियों की बहुलता है और जीवन यापन का मुख्य आधार प्राकृतिक संपदा पर निर्भर रहा है। जब से इस क्षेत्र के भूगर्भ में कोयले के अटूट भंडार, वन संपदा एवं जल की प्रचुर मात्रा आदि का पता चला तो, 1957 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया। इसके तुरंत बाद सन 1963 में से निकाला जा रहा कोयला, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों को भेजा जाने लगा। विद्युत संयंत्रों की स्थापना, कोयला क्षेत्र के समीप ज्यादा मितव्ययी होने के कारण रिहंद बांध परिक्षेत्र को प्रमुख ऊर्जा केंद्र हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। ऊर्जा की राष्ट्रीय राजधानी बनाने के दृष्टिकोण से विकसित यहां का अधिकांश भाग मध्यप्रदेश के सिंगरौली तथा कुछ भाग उत्तर प्रदेश के सोनमद्र जिले में आता है। रिहंद बांध परिक्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र की बिजली और कोयला बेचने से लगभग ६००० करोड़ का राजस्व पैदा होता है, परंतु विषमता देखिए नीति आयोग ने 2015 में देश के 20 अति पिछड़े जिलों में सिंगरौली

और सोनमद्र को शामिल किया है। सन् 1991 में विश्व बैंक और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) द्वारा गठित पर्यावरण आयोग ने पाया कि 90: स्थानीय समुदाय को यहां स्थापित विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों के कारण अनेक बार विस्थापित होना पड़ा है। इनमें से 35: लोगों को तीन बार विस्थापित होना पड़ा है। पिछले साल एस्सार, एन.टी.पी.सी., और रिलायंस पावर प्लांट के राखड़ बांध टूटने से 6 लोगों समेत दर्जनों मवेशी मारे गए और सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई और जमीन बंजर हो गई। 6 अक्टूबर 2018 को एन. टी.पी.सी. विंध्याचल का शाहपुर स्थित विशालकाय राखड़ बांध टूट गया था। जिससे 35 मैट्रिक टन राख, रिहंद बांध में समा गया जो नदी के पानी को जहरीला बना दिया। रेणुका नदी पर बने इस बांध से ही सोनमद्र और सिंगरौली जिले के लाखों लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है।

देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रिहंद बांध परिक्षेत्र, गहरे पर्यावरणीय संकट की ओर बढ़ रहा है, जो जमीन कमी घने जंगलों, वन्यजीवों और भारी वर्षा के कारण



बीहड़ और रहस्यमय मानी जाती थी, वह आज उजाड़ है। हवा में जहर घुल गया है और चारों तरफ कोयले की राख और धूल ने खेतों और पानी के स्रोतों को जहरीला बना दिया है। नदियां सूखती जा रही हैं और खेती की उपज आदि हो गई है। पूरी आबादी, फेफड़े और पेट की तरह-तरह की बीमारियों से ग्रसित है। बच्चे, कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ कोर कमेटी की रिपोर्ट भी यहां के मुसीबतों का कुछ ऐसा ही उल्लेख करती है। इस कमेटी के अनुसार इस क्षेत्र में 350 से अधिक उद्योग संचालित हैं। जिनमें 10 थर्मल पावर प्लांट, 16 कोयला खदानें 10 रसायन कारखाने, 8 विस्फोटक कारखाने, 309 क्रेशर और स्टील सीमेंट एवं एलमुनियम के एक-एक उद्योग हैं। इनसे करीब 45 लाख टन कचरा हर साल उत्सर्जित होता है। जिसमें लगभग 35 लाख टन तो सिर्फ कोयले की राख है। 21 हजार मेगा वाट बिजली उत्पादन करने के लिए साल भर में 10.3 लाख टन कोयले की जरूरत होती है इतनी बड़ी मात्रा में कोयले की खपत से हर साल 3.5 लाख टन राख पैदा हो रहा है, जिसका सही तरीके से निस्तारण नहीं हो पाता है। इसके अलावा 10 लाख टन से अधिक लाल कीचड़ रेड-मड तथा अन्य रसायन उत्सर्जित होते हैं। परंतु इनके निस्तारण के लिए उचित प्रबंध नहीं होने से 20 लाख टन से अधिक कचरा, सिंगरौली - रिहंद परिक्षेत्र में खुले में फेंका जा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार करीब 17 हजार टन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस हवा में तैरने के साथ ही हर साल 8.4 हजार टन यानी 8.4 लीटर मरकरी भी ऊर्जा संयंत्रों से निकल रहा है जो इस इलाके की जल-संरचनाओं में समाहित हो रही है। पारे की इतने बड़े पैमाने पर मौजूदगी मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी अधिक खतरनाक साबित हो रहा है।

हर चमकीली वस्तु का एक स्याह पक्ष जरूर होता है। सोनभद्र के रेणुकापार और रिहंद के ऊर्जाचल क्षेत्र में यहां के निवासियों की जीवन पर प्रदूषण का घना अंधेरा छाया हुआ है। हवा हो या फिर मिट्टी और पानी सब कुछ प्रदूषण की चपेट में है। एक तरफ प्रदूषित पानी पीकर लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषित हवा के लंबे संपर्क में रहने के कारण टी.बी., अस्थमा सी.ओ.पी.डी. जैसे रोग, आम जनमानस को कमजोर कर रहे हैं। कोयला और बिजली से जुड़ी परियोजनाओं ने स्थानीय निवासियों के जीवन में खुशहाली का उजाला भरने के वादे तो खूब किए थे, लेकिन खुद के स्थापित होने के बाद लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। उनके

हक हकूक की बातें करने वालों ने भी निजी फायदे के लिए कायदों से समझौता कर लिया है। आज नतीजा यह है कि देश के सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में शामिल रिहंद बांध परिक्षेत्र से सम्बंधित ऊर्जाचल के लोग हर रोज प्रदूषण का जहर हलक को नीचे उतारने के लिए मजबूर हैं। जिनके कुछ सर्वेक्षण तथा अध्ययनगत उदाहरण निम्नवत हैं।

**केस नंबर 1:-** वेदांती प्रजापति तथा उनके परिवार के घर और एन.सी.एल. की खदान के बीच 500 मीटर से भी कम की दूरी है। घर की छत से नजर दौड़ाएं तो चारों ओर दिखते हैं- आसमान छूते मिट्टी के विशाल पहाड़ जो एन.सी.एल. की कोयला खदानों से निकली राख है। बिना कोई सवाल पूछे, उनका पहला जवाब ही सारी कहानी कह देता है। "हमको कुछ नहीं कहना है साहब, कारखानों से भागते भागते हम थक चुके हैं। बांध बना तो घर डूब गया, बाप दादा हमें लेकर दूसरी बस्ती में बसे फिर एन.टी.पी.सी. ने प्लांट लगाया और हमें यहां भेज दिया। यहां से अब गुजारा मुश्किल है, बारिश में पहाड़ों की मिट्टी घरों में घुस आती है। खदानों में ब्लास्टिंग होती है तो भूकंप के जैसे पूरा घर हिलता है।" भगोड़ों सी जिंदगी और रोजी-रोटी की तलाश में भटकने का डर, वेदांती के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। लेकिन घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी खदान के घमाकों से चटकती दीवारों ने जिंदगी को इतना बेहाल कर दिया है कि किसी भी कीमत पर लोग बस्ती छोड़ देना चाहते हैं। विस्थापितों की सबसे बड़ी समस्या है कि कंपनियों की संख्या और खदानों का क्षेत्र लगातार बढ़ती जा रही है। एक कंपनी उन्हें विस्थापित कर जिस जगह बसाती है, वहीं दूसरी कंपनी का कारखाना उनके लिए बोरिया-बिस्तर बांधने के लिए विवश करता रहता है। प्रजापति की बातचीत में जो गुस्सा झलकता है वहीं चिल्काटांड के लगभग हर बाशिंदे की कहानी है। अपनी 8 साल की विकलांग बेटी को स्कूल से घर लाती एक महिला को रोक कर जब हमने बात करनी चाही, तो दो टूक जवाब मिला कि "हर कोई तो सर्वे करने चला आता है, लेकिन बदलता कुछ नहीं। पता नहीं कागजों में क्या लिखते हैं कि लखनऊ दिल्ली जाकर सब बातें पलट जाती हैं। हमारा नाम और पता मत लिखिएगा, कंपनी वाले कहते हैं कि विस्थापित गुंडागर्दी करते हैं, गलत बात फैलाते हैं।"

**केस नंबर दो:-** बांध विस्थापितों के गांव कुसमाहा में रहने वाले बृजमोहन की 43 साल की बेटी, मानसिक रोग से पीड़ित है। प्रदूषण के चलते इस इलाके में विकलांगता और मानसिक बीमारियों के मामले भी अधिक वृद्धि हुई हैं। बृजमोहन उस दिन को याद करते हुए कहते हैं- "विस्थापितों को अपनी जमीन से उजड़ने का दुख तो



था, लेकिन नेहरू जी ने कहा था कि देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाना है। गांव में बिजली आएगी और सबको नौकरी मिलेगी। 72 साल के बृजमोहन, आज भी उस बिजली का इंतजार कर रहे हैं। दिन ढले अंधेरे में लालटेन टटोलकर रोशनी करते हुए कहते हैं— हमारी उपजाऊ जमीन लेकर सरकार ने हमें यहां पठार में बसा दिया, हम आज भी हैंडपंप से पानी खींचकर खेत में सिंचाई करते हैं। यहां केवल सब्जी होती है और पैदावार इतनी ही है कि 3 लोगों का पेट भर जाए तो बड़ी बात है। कंपनी वालों ने घर के बराबर में बिजली का खंभा गाड़ा था, तार भी पड़े, लेकिन बिजली आज तक नहीं आई। “कोयले और पानी के खजाने से आबाद लेकिन बदहाल इस इलाके में लगभग सभी गांवों और बस्तियों की लगभग यहीं कहानी है। 1962 में जिस जगह रिहंद बांध बना, वह उस वक्त मिर्जापुर व सिंगरौली का सबसे बड़ा आबादी वाला इलाका था, जैसे ही सरकार को इस इलाके में फैले काले सोने की खबर लगी, देखते ही देखते 2200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कोयला की खदानें भी खुद गईं। 1951 जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त विस्थापितों की संख्या 1,05,000 थी।

**केस नंबर 3:**— अभी ज्यादा दिन नहीं बीते कि डिबुलगांज निवासिनी 50 वर्षीय पार्वती देवी सहजता से कोई भी कार्य कर लेती थी, किंतु अचानक उनके घुटनों में दर्द उठा, देखते ही देखते उन्हें चलने फिरने में परेशानी होने लगी। पार्वती देवी ने बताया कि काफी दवा कराने के बाद भी उनकी समस्या दूर नहीं हुई है। आज भी वे दर्द के मारे किसी प्रकार लगड़ा कर चलती हैं और अपना कार्य निष्पादित करती हैं। इस प्रकार यहां के निवासियों को प्रदूषण की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आ पा रहा है सब लोग भाग्य भरोसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं।

**केस नंबर- 4:**— इसी प्रकार, लोझरा निवासी सेवानिवृत्त, अनपरा परियोजना कर्मी राम दुलारे पनिका बिल्कुल स्वस्थ रहते हुए अपनी ड्यूटी कर ही रहे थे कि तभी अचानक सेवानिवृत्त होने के 6 वर्ष पूर्व ही पैरालिसिस के शिकार हो गए। काफी दवा कराने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। अंत में उनकी शेष ड्यूटी उनके पुत्र को करनी पड़ रही है। आज भी वह दूर तक आने-जाने में सक्षम नहीं हो सके हैं। इस प्रकार रिहंद बांध का परिक्षेत्र, प्रदूषण के त्रासदी से भयंकर रूप से ग्रस्त है। ज्यादातर बीमारियां पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण लोगों में फैल रही हैं।

**केस नंबर 5:**— नई बस्ती की मांग कर रहे चिल्काटांड निवासी मनोनीत कहते हैं “जहां आप खड़े हैं,

अगले साल यहां ब्लारिस्टिंग हो रही होगी। इसी तरह खदान लगातार आगे बढ़ती रहती है। सच तो यह है कि जिस जमीन पर विस्थापितों को बसाया जाता है, उसका मालिकाना हर कंपनी के पास ही रहता है। वह जब चाहे हमें हटा सकते हैं, जबकि विस्थापित न जमीन बेच सकते हैं ना उस पर कर्ज ले सकते हैं। कुल मिलाकर खेत मालिक से आज हम बेघर विस्थापित हो गए हैं। बार-बार विस्थापित होने की त्रासदी और सरकारों का उदासीन रवैया हमें आत्महत्या को मजबूर करता है। हम सबका जीवन नर्क हो गया है, यहां से बिजली पैदा होती है और पूरे देश में रोशनी होती है, लोगों में खुशी होती है। लेकिन अफसोस है कि हम लोगों का जीवन आज भी अंधेरे और अव्यवस्था के बीच बीत रहा है”।

**पर्यावरणीय प्रदूषण का स्वरूप—** वायु प्रदूषण— रिहंद बांध परिक्षेत्र में 24 घंटे छापे रहने वाले प्रदूषकों के सूक्ष्म तत्वों व लाई ऐश के कारण आम नागरिकों को सांस लेना भी भारी हो रहा है। आलम यह है कि रिहंद बांध, सिंगरौली व अनपरा परिक्षेत्र की एयर क्वालिटी इन्डेक्स 200 से अधिक ही बनी रहती है। वायु में कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फरडाईऑक्साइड, कार्बन, सल्फर और लेड आदि विषाक्त तत्वों की अधिकता के कारण, क्षेत्र में सांस से जुड़ी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और नागरिकों को अपना शिकार बना रही हैं।

**जल प्रदूषण—** औद्योगिक व रिहायशी अपशिष्टों के कारण पूरे रिहंद बांध के परिक्षेत्र का भूगर्भ जल स्रोत जहरीला हो चुका है। एन.जी.टी. के निर्देश पर कई ख्यातिलब्ध संस्थाओं ने क्षेत्र में पानी की जांच की है, पानी में मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, लोराइड, कार्बन और सल्फर आदि रसायन मानक से कई गुना अधिक पाए गए हैं। हजारों लोग द्वारा, इस प्रदूषित जल का सेवन करने से कई लाइलाज बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लगातार बढ़ता जल प्रदूषण लोगों में बीमारियां पैदा कर रहा है। लोग विशेषकर किडनी की बीमारियों और पेट संबंधी रोगों से पीड़ित हो रहे हैं।

**मृदा प्रदूषण—** ताप विद्युत परियोजनाओं के अपने ऐश पांड को मानक के अनुरूप दुरुस्त नहीं करने के कारण, क्षेत्र में कई स्थानों पर बिखरी रॉख, सहज ही देखी जा सकती है। इससे .वि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। फसलों में भी जहरीले रसायन प्रवेश कर रहे हैं। इसका नागरिकों के स्वास्थ्य पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रिहंद बांध परिक्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण खुले में कोयले व रॉख का परिवहन है। पिछले 1 वर्ष से हाईवे पर भी रॉख का परिवहन शुरू कर



दिया गया है। हालांकि इस संबंध में एन.जी.टी. ने बाकायदा गाइडलाइन निर्धारित किया है, इसके बावजूद, मानक का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। जल प्रदूषण के कारण रिहंद-डैम सहित नदी नालों में रॉख सहित अन्य अपशिष्टों का सीधे प्रवाह है। वैसे तो अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कई मानक तय किए गए हैं, लेकिन ज्यादातर परियोजनाओं में इसकी अवहेलना हो रही है।

**बीमारियों की भयावहता-** भीषण जल प्रदूषण के कारण, रेणुका पार इलाके में कुपोषण व अपंगता संबंधी मामले बढ़ रहे हैं। क्षेत्र के 70: से अधिक महिलाएं व बच्चे विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, साथ ही त्वचा संबंधी मामले भी निरंतर बढ़ रहे हैं। कम उम्र में ही दांत टूटना, असमय बालों का सफेद होना, शारीरिक रूप से कमजोर होना और मानसिक बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। टी.बी., कैंसर, अस्थमा, कुपोषण, हड्डियों का कमजोर होना, अपंगता इत्यादि बीमारियां भी हो रही हैं। रिहंद के किनारे बसे मकरा, सिंदूर, बेलवाहद जैसे गांव मच्छर जनित बीमारियों से जूझते रहते हैं। हर साल कई लोगों की जानें चली जाती हैं। यहां की औसत उम्र 65 से 70 वर्ष है। डिबुलगंज स्थित संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सक डॉ० बी.के. सिंह ने बताया कि ऊर्जाचल क्षेत्र में पहुंचकर, 5 साल तक जीवन बिताने के बाद, यहां के लोगों की उम्र तेजी से घटने लगती है। पानी और हवा में व्याप्त प्रदूषण के कारण, लोगों को तरह-तरह के रोग हो रहे हैं। इसमें दमा, टी.बी., बी.पी., शुगर, एलर्जी, चर्म रोग और दांतों के रोग आदि प्रमुख हैं। इन बीमारियों के बढ़ने का खतरा यहां अधिक है। पानी की गंदगी के कारण, शरीर के भीतर और हवा की गंदगी के कारण शरीर के ऊपरी भाग को पूरी तरह से प्रदूषण बर्बाद कर रहा है, जिससे यहां लोगों को 70 वर्ष से अधिक जीवन जीने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा है।

**निष्कर्ष-** रिहंद बांध परिक्षेत्र में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के लिए, विद्युत परियोजना के प्रबंधकों के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन कम जिम्मेदार नहीं है। उनकी ओर से अपनी जिम्मेदारियों का भली-भांति निर्वहन नहीं किया गया है। रही सही कसर कोयला व रॉख परिवहन में लगे वाहनों की जांच में उदासीनता बरत कर परिवहन विभाग ने पूरी कर दी है। रॉख से खाक होती जिंदगी को बचाने के लिए, कमेटी ने

कुछ सुझाव भी दिए हैं- पीने के पानी का किसी भी तरह से उद्योगों में इस्तेमाल नहीं हो। बांध के समीप सभी राखड़ बांध हटाए जाएं, कोयले की दुलाई किसी भी स्थिति में सड़क मार्ग से नहीं हो। सिंगरौली और सोनभद्र जिला निकाय, 'वाटर ट्रीटमेंट प्लांट' लगाएं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 'एंविरोट क्वालिटी सिस्टम' लगातार सक्रिय रखने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं। परंतु बीते 4 सालों में, इन सुझाव पर कोई अमल नहीं हुआ है। यदि हुआ होता तो राखड़ बांध फूटने जैसे हादसे से बचा जा सकता था। विकास में स्थानीय समुदाय की हिस्सेदारी जैसे सबालों पर वर्षों से केवल राजनीति हो रही है और विकास के नाम पर स्थानीय समुदाय की बलि चढ़ाई जा रही है। जानकारों का मानना है कि प्रदूषण पर प्रभावी रोक का सबसे सहज उपाय है- एन.जी.टी. के दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। हालांकि रिहंद बांध परिक्षेत्र के सम्पूर्ण प्रदूषण को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, मगर भावी पीढ़ी के लिए उन पर अंकुश अवश्य लगाया जा सकता है और पर्यावरण में सुधार कर एक बेहतर जीवन की कामना का प्रयास तो अवश्य ही किया जा सकता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बदहाली के आंसू रोता नेहरू का स्विट्जरलैंड -बी.बी.सी. न्यूज <https://www-bbc-com/2012/10/2010>
2. देश को रोशन करने वाले सोनभद्र में बीमारी और मौत [https://www-bbc-com>Uttar &pradesh&election>up...](https://www-bbc-com/Uttar&pradesh&election>up...)
3. नाराज हुआ रिहंद, तो आधे भारत में हो जाएगा अंधेरा <https://www-patrika-com>over polluted rihand dam/...>
4. सिंगरौली पार्ट- 2 राख खाते हैं, राख पीते हैं, राख में जीते हैं। 24 अक्टूबर, 2017 <https://gaon connection-com>Read>ns'k>
5. अमर उजाला, 15 जून, 2017 पृष्ठ -9
6. रिहंद का स्याह सच, सर्वोदय प्रेस सर्विस, 12 अक्टूबर, 2018 <https://2-www-spsmedia-in/dam&and&displacement/the&truth& of&singrauli&rihand&dam/>

\*\*\*\*\*